Categories of coal	Price of ROM coal as in July '95	Price of ROM coal as in July'96		
		For companies other than MCL & WCL	For MCL	For WCL
Semi-Coking-II	628	785	785	785
Non-Coking coal				
Gr. A	642	771	739	936
Gr. B	586	692	663	880
Gr. C	513	590	565	795
Gr. D	406	406	406	584
Gr. E	322	322	322	486
Gr. F	257	257	257	405
Gr. G	183	183	183	305

(d) Increase in prices of coal are necessitated by the increase in the various input costs as well as wage increase etc. The increase in price of the above nature is beyond the control of the coal industry. To some extent, however, the effect of the increase in input cost can be offset by increasing productivity. CIL and SCCL are continuing to take steps to increase productivity and are focusing on better capacity utilisation of heavy earth moving machinery and increase in output per man-shift.

माल-डिब्बों की कमी के कारण कोयले की ढुलाई न किया जाना

3455. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड माल-डिब्बों की कमी के कारण कोयले की ढुलाई का लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कोल इंडिया लिमिटेड को कोयले की ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में माल डिब्बे उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

कोयला मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) वर्ष 1995-96 के लिए प्रतिदिन 18058 चार पहिया वैगन (एफ०डब्ल्यू०डब्ल्यू०) के दैनिक लदान लक्ष्य की तुलना में वास्तविक दैनिक लदान 16900 एफ०डब्ल्यू०डब्ल्यू प्रतिदिन हुआ है। इस संबंध में कमी रही है।

(ग) वैगनों की उपलब्धता में सुधार लाए जाने के लिए कोयला कंपनियों और क्षेत्रीय रेलवे के बीच क्षेत्र स्तर पर निकटतम सम्पर्क रखा जा रहा है। रेल द्वारा कोयले के संचलन पर भी एक अंतर-मंत्रालीय बैठक में नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है और जहां भी अपेक्षित होता है, सुधारक उपाय किए जाते हैं।

Protection of Workers Under I.D. Act, 1947

3456. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether the Industrial Disputes Act, 1947, provides for certain measures of protection to the workers in the -event of lay off, retrenchment and closure;

(b) if so, whether- Government have any information about the units effecting retrenchment -and workers retrenchment during the last three years in the State of Maharashtra, year-wise and district-wise; and

(c) in what manner Government had ensured that the protection measures of Industrial Disputes' Act were made available to these retrenched workers in the State?